गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 245
दि. 05.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

गोलियों की गूंज में बुझती जिंदगियां, उत्तरी नाइजीरिया का एक और गांव हिंसा की भेंट चढ़ा

(जीएनएस)। नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से से आई ताज़ा खबर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह इलाका आज भी भय, असुरक्षा और हिंसा के साए में जीने को मजबूर है। नाइजर राज्य के कसुवान-दाजी गांव में शनिवार शाम जो हुआ, वह किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गहरी चिंता और शर्म का विषय है। हथियारबंद हमलावरों ने अचानक गांव में धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 30 से अधिक निर्दोष लोगों की जान ले ली। यह सिर्फ आंकड़ों की खबर नहीं है, बल्कि उन टूटे घरों, उजड़े परिवारों और सहमी हुई जिंदगियों की कहानी है, जिनका भविष्य एक ही शाम में अंधेरे में डूब गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही शाम ढलने लगी और लोग अपने रोज़मर्रा के काम निपटाकर घरों की ओर लौट रहे थे, तभी गोलियों की आवाज़ ने पूरे गांव को दहशत में बदल दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जान बचाने के लिए घरों में छिपे, कुछ खुले मैदानों की ओर भागे, लेकिन हमलावरों की गोलियों से कोई भी सुरक्षित नहीं रह सका। कुछ ही मिनटों में गांव की गलियों में चीख-पुकार मच गई और जमीन पर लाशें गिरने लगीं।

हमलावरों ने सिर्फ लोगों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि गांव की जीवनरेखा को भी तोड़ दिया। बाजार, जहां रोज़मर्रा की जरूरतों की खरीद-फरोख्त होती थी और जहां लोगों की मुलाकातें, बातचीत और जीवन की हलचल बसती थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया, जिससे जो लोग जान बचाने में सफल रहे, वे भी बेघर हो गए। रात होते-होते कसुवान-दाजी एक जीवित गांव से बदलकर खामोश खंडहर में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए अब तक 30 लोगों की मौत की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोगों का दर्द इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा है। गांव वालों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 37 या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। कई परिवार ऐसे हैं, जिनके एक से अधिक सदस्य हमले के बाद से नहीं मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ ग्रामीणों को हमलावर अपने साथ अगवा कर जंगलों की ओर ले गए हैं, जो इस इलाके में सक्रिय गिरोहों की आम रणनीति मानी जाती है।

नाइजीरिया में बढ़ता आतंक: डाकुओं के हमलों का कहर

उत्तरी नाइजीरिया में सशस्त्र "डाकू" गिरोह आतंक फैला रहे हैं, जिससे सामूहिक हत्याएं, अपहरण और विस्थापन हो रहा है। यह खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

कासुवन दाजी नरसंहार: एक केस स्टडी

गाँव के बाज़ार पर हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत

हमलावरों ने बाजार में आग लगा दी, दुकानें लूटीं और कई अन्य लोगों का अपहरण कर लिया।

हमलावर अमेरिका समर्थित हवाई हमलों से भाग रहे थे

नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवादी सोकोटो और ज़ाम्फ़ारा राज्यों से भाग रहे थे।

हत्या के क्रूर तरीके अपनाए गए

कई पीड़ितों को मारने या गोली मारने से पहले उनके हाथ बांध दिए गए थे।

एक व्यापक संकट: किसानों पर कहर

हर महीने औसतन **122 किसानों की हत्या** (अगस्त 2021-जुलाई 2022)

डाकुओं द्वारा किसानों को विस्थापित किया जाता है, उन पर टैक्स लगाया जाता है और उनकी आजीविका नष्ट कर दी जाती है।

हर महीने औसतन **87 किसानों का अपहरण** (अगस्त 2021-जुलाई 2022)

फिरौती के लिए अपहरण इन सशस्त्र समूहों के लिए एक आकर्षक व्यवसाय बन गया है।

किसानों की हत्या (अगस्त 2021 - जुलाई 2022)

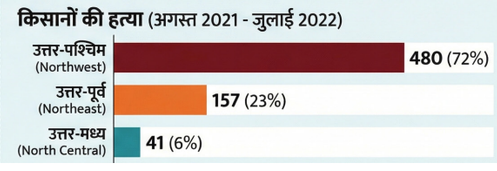

इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमले के काफी समय बाद तक भी पुलिस या सेना गांव नहीं पहुंची। जब तक सुरक्षा बल मौके पर आए, तब तक हमलावर अपने मंसूबे पूरे कर चुके थे और घने जंगलों की ओर फरार हो गए थे। इस देरी ने लोगों के मन में गुस्सा और डर दोनों को और गहरा कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर सुरक्षा बल पहुंच जाते, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में जानें न जातीं।

उत्तरी नाइजीरिया लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा की चपेट में है। यहां हथियारबंद गिरोह, डाकू और अपराधी समूह सक्रिय हैं, जो गांवों पर हमले, लूटपाट, हत्याएं और फिरौती के लिए अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। घने जंगल और दुर्गम इलाके इन अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं। पुलिस के अनुसार, कसुवान-दाजी पर हमला करने वाले हमलावर नेशनल पार्क फॉरेस्ट और काबे जिले की ओर से आए थे। ये इलाके इतने घने और दुर्गम हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए यहां प्रभावी कार्रवाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इस हिंसा का सबसे गहरा असर उन आम लोगों पर पड़ा है, जिनका इस संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं है। जिन बच्चों ने अपने सामने अपने माता-पिता, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को गिरते देखा, उनके मन पर यह डर शायद जीवन भर का निशान छोड़ जाएगा। महिलाएं अपने अगवा किए गए परिजनों की सलामती के लिए रो-रोकर दुआ मांग रही हैं, वहीं पुरुष अपने जले हुए घरों और उजड़ी आजीविका को देखकर बेबस खड़े हैं। खेती और पशुपालन पर निर्भर इस गांव की आर्थिक रीढ़ भी इस हमले से टूट गई है। लोग अब खेतों में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हर रास्ता और हर झाड़ी उन्हें खतरे से भरी नजर आती है।

नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और आर्थिक रूप से भी महाद्वीप में उसकी अहम भूमिका है, लेकिन ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या विकास और सुरक्षा का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है। कसुवान-दाजी की त्रासदी यह दिखाती है कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करते हैं। जब तक इन इलाकों में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावी प्रशासन और लोगों के लिए भरोसे का माहौल नहीं बनेगा, तब तक ऐसे हमले रुकना मुश्किल है।

कसुवान-दाजी में बहा खून केवल एक गांव की कहानी नहीं है। यह उन सैकड़ों गांवों की आवाज़ है, जो हर दिन इसी डर के साथ जीते हैं कि अगला हमला कब और कहां होगा। यह घटना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब सिर्फ बयान और आश्वासन काफी नहीं हैं। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि मासूम लोगों की जान की कीमत आंकड़ों तक सीमित न रह जाए और उत्तरी नाइजीरिया की धरती पर एक दिन सचमुच शांति लौट सके।

क्षेत्रीय सुरक्षा और भरोसे की नई इबारत, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का UAE और श्रीलंका दौरा

(जीएनएस)। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा को भारत की बदलती और सक्रिय रक्षा कूटनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। 5 से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मित्र देशों के साथ सैन्य विश्वास, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देना है। ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया की सामरिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, भारतीय सेना प्रमुख की यह यात्रा भारत की स्पष्ट मंशा और दूरदर्शी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। यात्रा के पहले चरण में जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उनका औपचारिक और सम्मानपूर्ण स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाना प्रस्तावित है। यह सम्मान केवल एक सैन्य परंपरा नहीं, बल्कि भारत और UAE के बीच गहराते रक्षा संबंधों का प्रतीक भी है। UAE में प्रवास के दौरान सेना प्रमुख वहां के सशस्त्र बलों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से विस्तृत बातचीत करेंगे। इन बैठकों में दोनों

देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही जनरल द्विवेदी प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे और अधिकारियों व जवानों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर पर अनुभव साझा करेंगे। यह संवाद केवल रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर समझ और आपसी सम्मान को और मजबूत करेगा। UAE के बाद सेना प्रमुख का दौरा श्रीलंका की ओर बढ़ेगा, जो भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार है। 7 और 8 जनवरी को श्रीलंका में जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात वहां की सेना के कमांडर, रक्षा उप मंत्री और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से होगी। इन चर्चाओं में द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है और यह यात्रा उस सहयोग को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। श्रीलंका प्रवास के दौरान सेना प्रमुख वहां के प्रतिष्ठित रक्षा शिक्षण संस्थानों, डीएससीएससी और बटला स्थित सेना युद्ध महाविद्यालय का भी दौरा करेंगे। यहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों से संवाद करेंगे और बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों और नेतृत्व की भूमिका जैसे विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इस प्रकार का संवाद न केवल ज्ञान का आदान-प्रदान होता है, बल्कि भविष्य के सैन्य नेतृत्व को एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।

भारतीय सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह पूरी यात्रा मित्र देशों के साथ भरोसे और सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि वह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने पड़ोसी व साझेदार देशों के साथ मिलकर इन उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह दौरा इसी सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें सैन्य कूटनीति को केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि विश्वास निर्माण और साझा सुरक्षा के साधन के रूप में देखा जा रहा है।

कुल मिलाकर, सेना प्रमुख की UAE और श्रीलंका यात्रा भारत की उस रणनीतिक नीति को सामने लाती है, जिसमें मित्र देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है और क्षेत्रीय सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी के रूप में समझा जाता है। यह दौरा न केवल वर्तमान रक्षा संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सैन्य साझेदार के रूप में और अधिक स्थापित करेगा।

धर्म और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरा जनाक्रोश
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ धनबाद में गूंजा विरोध

(जीएनएस)। धनबाद की सड़कों पर रविवार को असामान्य हलचल देखने को मिली, जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। सनातन धर्म जागरण समिति के आह्वान पर रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित आक्रोश प्रदर्शन और धरना केवल एक स्थानीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह उस पीड़ा, चिंता और असंतोष की अभिव्यक्ति बन गया, जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग के मन में लंबे समय से पल रही है। सुबह से ही चौक पर लोगों का जुटना शुरू हो गया था और धीरे-धीरे यह स्थल नारों, तख्तियों और भावनात्मक भाषणों का केंद्र बन गया।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा शामिल हुए। मंच पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के कई प्रमुख चेहरे मौजूद थे, जिनमें सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने एक स्वर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता जताई और इसे केवल किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताया।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि मई 2024 से बांग्लादेश में हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने, हिंदू घरों और दुकानों में लूटपाट, महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल तथा जबरन पलायन जैसी घटनाओं का उल्लेख किया। वक्ताओं का कहना था कि ये घटनाएं केवल छिटपुट नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे वातावरण की ओर इशारा करती हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और सम्मान दे, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।

धरना स्थल पर मौजूद लोगों की भावनाएं केवल नारों तक सीमित नहीं थीं। कई वक्ताओं ने भावुक शब्दों में कहा कि भारत और बांग्लादेश का इतिहास, संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना लंबे समय से जुड़ा रहा है, ऐसे में वहां हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं भारतीय समाज को भी भीतर तक आहत करती हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी समुदाय को डराना, उसकी आस्था के प्रतीकों को नष्ट करना और उसे पलायन के लिए मजबूर करना सभ्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

प्रदर्शन के बाद माहौल और भी तीखा हो गया, जब आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। यह कदम प्रतीकात्मक था, लेकिन इसके पीछे का संदेश स्पष्ट था—लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और वहां के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पुतला दहन के दौरान नारेबाजी हुई, लेकिन आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न रहा।

इसके पश्चात प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वह कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।

नेताओं और आयोजकों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके, तो यह आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसे राज्य स्तर से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा और व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। उनका कहना था कि यह किसी राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं, बल्कि धर्म, मानवता और न्याय से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर चुप रहना अपराध के समान होगा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान भावनाएं तीव्र थीं, फिर भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रित रही और कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। आयोजन के शांतिपूर्ण समापन के बाद भी यह स्पष्ट था कि यह प्रदर्शन केवल एक दिन का आक्रोश नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक विमर्श की शुरुआत है।

कानून के रक्षक कटघरे में, वैशाली में छापेमारी के नाम पर विश्वास का संकट

(जीएनएस)। वैशाली जिले से सामने आया ताजा मामला न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि आम जनता और कानून के बीच भरोसे की डोर को भी झकझोर देता है। लालगंज थाना क्षेत्र में की गई एक छापेमारी अब पुलिस विभाग के लिए ही संकट का कारण बन गई है। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान लाखों रुपये नकद और भारी मात्रा में सोना-चांदी गायब कर दिया गया, जिसका कहीं कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। मामला उजागर होते ही जिले में हड़कंप मच गया और अंततः पुलिस अधीक्षक को कड़ा कदम उठाते हुए थानाध्यक्ष और एक दारोगा को निलंबित करना पड़ा। घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है, जब लालगंज थाना पुलिस ने हाजीपुर के बिलनपुर गांव में कुख्यात चोर रामप्रीत सहनी के घर छापेमारी की थी। उस समय पुलिस की ओर से दावा किया गया कि घर से चोरी के बर्तन, एक टीवी, कारतूस और कुछ अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई सामान्य पुलिस प्रक्रिया के तहत दिखाई गई, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मामला अचानक गंभीर मोड़ ले बैठा। आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि छापेमारी के दौरान घर से सिर्फ वही सामान नहीं, बल्कि लाखों रुपये नकद, लगभग दो किलोग्राम सोना और करीब छह किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई थी।

परिजनों का आरोप है कि यह कीमती सामान जानबूझकर जब्ती सूची में शामिल नहीं किया गया और पुलिस टीम इसे अपने साथ ले गई। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाए, तो उन्हें टाल दिया गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। धीरे-धीरे यह चर्चा पूरे इलाके में फैल गई कि छापेमारी के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग खुलकर यह सवाल पूछने लगे कि अगर पुलिस ही इस तरह से बरामदगी को छिपाने लगे, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे। शिकायतों के सामने आने के बाद वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी की आशंका पुख्ता होने पर एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दारोगा सुमन झा को निलंबित कर दिया। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि विभाग इस मामले को दबाने के बजाय इसकी तह तक जाना चाहता है।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जा रही है। यह भी देखा जाएगा कि छापेमारी के दौरान वास्तव में क्या-क्या बरामद हुआ था, जब्ती सूची में क्या दर्ज किया गया और कथित रूप से गायब बताए जा रहे गहनों व नकदी का सच क्या है। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है।

यह मामला केवल दो अधिकारियों के निलंबन तक सीमित नहीं है। यह पुलिस की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। छापेमारी जैसी संवेदनशील कार्रवाई में अगर बरामद सामान का सही रिकॉर्ड न हो और उस पर संदेह पैदा हो जाए, तो यह पूरे तंत्र पर सवालिया निशान लगा देता है। वैशाली की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कानून का पालन कराने वालों पर जनता का भरोसा तभी कायम रह सकता है, जब वे स्वयं कानून और नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरें। अब सबकी नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि यह मामला महज आरोप है या पुलिस व्यवस्था में छिपी किसी गहरी बीमारी का संकेत।

नारी सम्मान के सवाल पर सड़कों पर उतरी भाजपा, पहाड़ की बेटी के नाम पर कांग्रेस पर राजनीति का आरोप

(जीएनएस)। हरिद्वार जिले के रुड़की में रविवार को राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया, जब महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और पहाड़ की बेटी की दुखद मौत पर राजनीति करने के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि यह विरोध केवल औपचारिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर भी गहरा है। हाथों में तख्तियां, नारों से गूंजता चौक और कांग्रेस के पुतले को आग के हवाले करने का दृश्य यह दर्शा रहा था कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितना आक्रोशित है।

रविवार की दोपहर जैसे-जैसे भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी चंद्रशेखर चौक पर एकत्र होने लगे, माहौल में तनाव और आक्रोश साफ झलकने लगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल पर आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की संवेदनशीलता और नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नारेबाजी के बीच कांग्रेस के खिलाफ पुतला दहन किया गया और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के संकल्प को दोहराया गया।

इस दौरान रुड़की भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह ने कहा कि पहाड़ की बेटी की मौत जैसे अत्यंत संवेदनशील और पीड़ादायक विषय पर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा राजनीतिक बयानबाजी करना उनकी मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जिस घटना पर पूरे समाज को संवेदना और आत्ममंथन की आवश्यकता है, उस पर राजनीति करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि महिलाओं के दर्द का अपमान भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी और इस तरह की बयानबाजी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलकमल ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटी केवल एक परिवार की बेटी नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। उसकी मृत्यु पर राजनीति करना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। नीलकमल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की भाषा और सोच महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रही है और यही कारण है कि बार-बार ऐसे बयान सामने आते हैं, जो नारी सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और कहा कि जब तक माफी नहीं मिलती, तब तक विरोध जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे, जिनमें जिला महामंत्री सागर गोयल, अक्षय प्रताप सिंह, राज्यमंत्री शोभाराम प्रजापति, श्यामवीर सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनीश गॉड, किसान मोर्चे के प्रदेश महामंत्री देवी सिंह राणा, जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नितिन गोयल, मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, आलोक गौतम, अनुज त्यागी, कार्यालय सह प्रभारी अंकित गौतम सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल रहीं। सभी ने एक स्वर में कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है।

संपादकीय

स्वच्छ पानी को मिले कानूनी हक: दूषित पेयजल से उपजता राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट

भारत ने बीते वर्षों में अपने पर्यावरणीय संकटों को मापने और समझने की एक व्यवस्थित भाषा विकसित की है। वायु प्रदूषण को एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिये हर दिन मापा जाता है, हीटवेव और बाढ़ जैसी आपदाएं राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी हैं और जलवायु परिवर्तन को लेकर नीतिगत स्तर पर भी सक्रियता दिखती है। लेकिन जब पीने का पानी ही बीमारी और मौत का कारण बन जाता है, तब हमारी प्रतिक्रिया न सिर्फ देर से आती है, बल्कि अक्सर अस्थायी और सीमित भी होती है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई हालिया मौतें किसी एक शहर या एक प्रशासनिक चूक की कहानी नहीं हैं, बल्कि उस गहरे और लंबे समय से चले आ रहे संकट का संकेत हैं, जिसे हम लगातार नजरअंदाज करते रहे हैं।

इंदौर की यह घटना देश के विभिन्न हिस्सों में पहले घट चुकी समान त्रासदियों की कड़ी का ही एक और अध्याय है। गुजरात के महिसागर जिले में हाल के महीनों में पीलिया का प्रकोप सामने आया, जिसकी जड़ बोरवेल और नगरपालिका जलस्रोतों का दूषित होना पाया गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में प्रदूषित नल का पानी पीने से बड़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। ओडिशा के संबलपुर में 2014 में फैले हेपेटाइटिस के प्रकोप ने लगभग 3,900 से अधिक लोगों को संक्रमित किया और करीब 36 लोगों की जान ले ली। ये घटनाएं बताती हैं कि असुरक्षित पेयजल कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक बार-बार उभरने वाला राष्ट्रीय संकट है।

इस संकट का पैमाना आंकड़ों में और भी भयावह दिखता है। 2005 से 2022 के बीच भारत में तीव्र दस्त, टाइफाइड, वायरल हेपेटाइटिस और हैजा जैसी प्रमुख जलजनित बीमारियों के 20.98 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 50,000 से अधिक मौतें हुईं। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार हर साल लगभग दो लाख लोग सुरक्षित पेयजल की अपर्याप्त उपलब्धता या खराब गुणवत्ता के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद जल गुणवत्ता कभी भी उतनी राजनीतिक या नीतिगत प्राथमिकता नहीं बन पाती, जितनी अन्य पर्यावरणीय संकेतक बनते हैं।

वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। अनुमान है कि देश के लगभग 70 प्रतिशत जलस्रोत किसी न किसी रूप में दूषित हैं। इसका सीधा असर जनस्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्पादकता पर पड़ता है। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां काम के दिनों की हानि, बढ़ते चिकित्सा खर्च और श्रम उत्पादकता में गिरावट का एक ऐसा दुष्चक्र पैदा करती हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और कमजोर वर्गों को होता है। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार इससे हर साल लगभग 3.77 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और करीब 7.3 करोड़ कार्यदिवसों का नुकसान होता है।

अक्सर यह मान लिया जाता है कि समस्या केवल जलस्रोतों में है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार पानी की गुणवत्ता उस यात्रा के दौरान बिगड़ती है, जो वह स्रोत से नल तक तय करता है। देश के अनेक शहरों में यह पाया गया है कि सीवर का पानी पेयजल पाइपलाइनों में मिल जाता है। यह शहरी शासन की एक जानी-पहचानी विफलता है। नगरपालिका के अलग-अलग विभाग अक्सर आपस में समन्वय के बिना काम करते हैं। सड़क निर्माण एजेंसियां बिना जल और सीवरेज विभागों से तालमेल किए खुदाई कर देती हैं, जिससे भूमिगत पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। भूमिगत उपयोगिताओं के सटीक और साझा नक्शों के अभाव में भारी मशीनें पेयजल पाइपों को तोड़ देती हैं या सीवर लाइनों को नुकसान पहुंचाती हैं। नतीजतन गंदा पानी साफ पानी की लाइनों में प्रवेश कर जाता है और समस्या तब सामने आती है, जब लोग बीमार पड़ने लगते हैं या जान चली जाती है। यह समन्वयहीनता शहरी अवसंरचना कार्यक्रमों के विस्तार के साथ और गंभीर होती जा रही है। कई बार नई पाइपलाइनें तो बिछा दी जाती हैं, लेकिन नीचे मौजूद पुरानी, जर्जर और रिसती हुई नेटवर्क व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

भारत तेजी से शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में सुरक्षा प्रोटोकॉल, निरंतर निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। जल क्षेत्र की सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी स्वतंत्र नियमन का अभाव है। बिजली क्षेत्र में राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाए गए, ताकि सेवा प्रदाय और नियमन को अलग किया जा सके और मानकों का सख्ती से पालन हो।

आस्था और सृजन की शक्ति का प्रतीक सोमनाथ, आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है मंदिर

> सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक है, जिसने विदेशी आक्रमणों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। 1026 में महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल और 1951 में पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर, यह मंदिर विध्वंस पर सृजन की शक्ति का संदेश देता है। सरदार पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के स्वाभिमान और अटूट विश्वास का प्रतीक है।

सोमनाथ... यह शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ भारत के आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतीकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का स्थान सबसे पहले होता है।

दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बनता रहा। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है।

उस दौरान क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है, जिनकी पीड़ा की अनुभूति आज तक होती है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी है। 11 मई, 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति में वह ऐतिहासिक समारोह आयोजित हुआ, जब पुनर्निर्मित मंदिर को दर्शनों के लिए खोला गया।

वर्ष 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण के लिए उकसाने का काम किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था, पर हर बार जब भी मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे वीरों-वीरांगनाओं ने उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया। सोमनाथ की आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

महमूद गजनवी लूटकर चला गया, मगर सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, विश्वास और प्रबल हुआ। वर्ष 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वह आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हमारी शक्ति का पुंज है। सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है।

हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरा पर जीवन पाया, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे। वहां के अनुभव पर 1897 में चेन्नई में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार-बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त-जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।'

स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने सक्रियता से यह दायित्व संभाला। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण से बहुत उत्साहित नहीं थे और नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। हालांकि राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख केएम मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल' अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि हम ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, किंतु उसकी चेतना अमर रही। इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने की शक्ति दी। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प से आज भारत पर विश्व की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। हमारी कला, संस्कृति, संगीत और पर्व-त्योहार आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है।

अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ का प्रतीक यही दर्शाता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।

प्रेरणा

अडिग संकल्प से दौड़ती विजय

जीवन में कभी-कभी ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं, जो केवल प्रेरणा नहीं देतीं, बल्कि मनुष्य की सीमाओं को ही चुनौती दे देती हैं। वे यह प्रमाणित करती हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी क्रूर क्यों न हों, यदि संकल्प अडिग हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। ऐसी ही एक विलक्षण और रोमांचक गाथा है अमेरिका की महान धाविका एलिजाबेथ "बेट्टी" रॉबिन्स की, जिनका जीवन स्वयं में साहस, संघर्ष और विजय का जीवंत प्रतीक है।

एलिजाबेथ रॉबिन्स का जीवन आरंभ से ही किसी असाधारण कहानी की तरह नहीं था। वह एक सामान्य अमेरिकी परिवार की बेटी थीं। स्कूल जाना, पढ़ाई करना और समय पर घर लौटना उनका रोज़मर्रा का जीवन था। फर्क बस इतना था कि वह हर काम में तेज़ थीं। स्कूल से लौटते समय वह अकसर दौड़कर ट्रेन पकड़ती थीं। यह उसकी मजबूरी भी थी और आदत भी। लेकिन यही साधारण-सी आदत उसके जीवन की दिशा बदल देगी, इसका उसे स्वयं भी अनुमान नहीं था।

एक दिन स्कूल के अध्यापक चार्ल्स प्राइज की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह किशोरी दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ दौड़ती है। जिज्ञासावश उन्होंने स्टॉपवॉच से उसकी गति नापी और चौंक गए। उनकी प्रशिक्षित आँखों ने तुरंत पहचान लिया कि इस बच्ची के भीतर असाधारण प्रतिभा छिपी है। चार्ल्स प्राइज ने एलिजाबेथ से बात की और उसे व्यवस्थित प्रशिक्षण देने का निश्चय किया। यह वही क्षण था, जब एक साधारण छात्रा के भीतर एक ओलंपिक चैंपियन का बीज अंकुरित हुआ।

एलिजाबेथ उस समय महज़ पंद्रह वर्ष की थी। नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठोर मेहनत ने बहुत जल्दी असर दिखाया। कुछ ही महीनों में उसने स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। जल्द ही वह 100 मीटर की दौड़ में अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका हेलेन फिल्की के साथ मैदान में उतरी। यह मुकाबला उसके लिए परीक्षा जैसा था। पहली दौड़ में वह दूसरे स्थान पर रही, लेकिन उसने हार को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। तीन महीने बाद, जब वही दोनों धाविकाएँ फिर आमने-सामने थीं, एलिजाबेथ ने हेलेन फिल्की को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। यहीं से उसके स्वर्णिम सफर की शुरुआत हुई।

एम्सटर्डम ओलंपिक की तैयारियाँ शुरू हुईं। अमेरिका की ओर से 100 मीटर दौड़ के लिए एलिजाबेथ क्वालिफाई करने वाली एकमात्र धाविका बनीं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। ओलंपिक का मंच, हजारों दर्शक, दुनिया भर की निगाहें—इन सबके बीच एलिजाबेथ ने अद्भुत संयम और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उसने रेस जीती और मात्र सोलह वर्ष की आयु में 100 मीटर ओलंपिक चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वह उस समय की सबसे कम उम्र की ओलंपिक विजेताओं में शामिल हो गई।

जहाँ भी एलिजाबेथ दौड़तीं, इतिहास रच देतीं। अख़बारों में उनकी तस्वीरें छपने लगीं, लोग उन्हें "दौड़ती हुई बिजली" कहने लगे। लेकिन जीवन केवल प्रशंसा और सफलता की सीधी रेखा नहीं होता। नियति ने उसकी राह में एक ऐसी परीक्षा रखी, जिसने किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ दिया होता।

जून 1931 का वह दिन उसके जीवन का सबसे भयावह मोड़ बन गया। एलिजाबेथ अपने भाई के निजी जहाज़ में उड़ान भर रही थीं। लगभग 600 मीटर की ऊँचाई पर जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चारों ओर चीख-पुकार, धुआँ और मलबा था। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचा, तो सभी को लगा कि एलिजाबेथ अब जीवित नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, अचानक उनके शरीर में हल्की-सी हरकत हुई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।

हालाँकि उनका शरीर बुरी तरह टूट चुका था। दोनों टांगों और बाहों की हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थीं। डॉक्टरों ने पूरी ईमानदारी से लेकिन निर्ममता के साथ कह दिया—"अब तुम कभी चल नहीं सकोगी।" यह वाक्य किसी के भी मनोबल को चकनाचूर कर सकता था। लेकिन एलिजाबेथ रॉबिन्स साधारण इंसान नहीं थीं। उन्होंने इस भविष्यवाणी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।

अस्पताल के बिस्तर पर लेटे-लेटे भी उनके भीतर वही धाविका जीवित थी। असहनीय दर्द, लंबा इलाज और निराशाजनक हालात—इन सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पहले बैसाखियों के सहारे खड़ी हुईं, फिर धीरे-धीरे चलना सीखा। हर कदम पर पीड़ा थी, लेकिन हर कदम के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। चार वर्षों का कठिन संघर्ष, अनगिनत आँसू और अथक परिश्रम—इन सबके बाद वह दिन आया, जब एलिजाबेथ फिर से ट्रैक पर उतरी।

8 अगस्त 1936, बर्लिन ओलंपिक। दुनिया की निगाहें स्टेडियम पर टिकी थीं। वही एलिजाबेथ, जिसे कभी चलने से मना कर दिया गया था, अब फिर से 100 मीटर की दौड़ के लिए तैयार खड़ी थी। स्टार्ट की आवाज़ हुई और वह पूरी शक्ति के साथ दौड़ पड़ी। कुछ ही सेकंड में उसने फिनिश लाइन पार कर ली। एलिजाबेथ "बेट्टी" रॉबिन्स ने दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम कर इतिहास रच दिया। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह मानवीय इच्छाशक्ति की विजय थी। एलिजाबेथ की कहानी आज भी यह सिखाती है कि गति केवल पैरों की ताकत नहीं होती, बल्कि वह आत्मा की दृढ़ता से जन्म लेती है। जिसने परिस्थितियों से हार मानने से इनकार कर दिया, वही सच्चा विजेता बनता है। अडिग संकल्प से दौड़ती यह विजय आज भी हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है।

पेयजल की गुणवत्ता पर उठते रहे हैं सवाल, इंदौर जैसी घटना न होने तक सोता है प्रशासन

इंदौर के बाद बेंगलुरु और गांधीनगर में दूषित पेयजल की आपूर्ति की खबरें सामने आना किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गहरे आत्ममंथन का विषय होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ऐसी खबरें अब चौंकाती नहीं हैं। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमने पानी जैसी सबसे बुनियादी आवश्यकता को भी गंभीरता से लेना लगभग छोड़ दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 16 लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार पड़ने की घटना केवल एक स्थानीय हादसा नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की शहरी व्यवस्था, प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर कठोर प्रश्नचिह्न लगाती है।

भारत में पेयजल की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। अनेक सरकारी और गैर-सरकारी शोध, सर्वेक्षण और रिपोर्ट बार-बार यह चेतावनी देती रही हैं कि देश के बड़े हिस्से में लोगों को जो पानी पीने के लिए मिल रहा है, वह स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद नगर निगमों, नगर पालिकाओं और राज्य सरकारों की सक्रियता तब तक दिखाई नहीं देती, जब तक कोई बड़ी त्रासदी घटित न हो जाए। इंदौर की घटना इसी प्रशासनिक निष्क्रियता का भयावह उदाहरण है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर यदि सुरक्षित पेयजल तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, तो बाकी शहरों की स्थिति की कल्पना करना कठिन नहीं है।

इतनी बड़ी त्रासदी के बाद प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए गए, वे भी औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पाए। पहले दो अधिकारियों को निलंबित किया गया, फिर मौतों का आंकड़ा बढ़ने पर कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कुल मिलाकर यह कार्रवाई केवल निलंबन तक ही सीमित रही। न तो किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, न ही ऐसी कठोर कार्रवाई देखने को मिली जो भविष्य में दूसरों के लिए चेतावनी बन सके। यह रवैया दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव किस हद तक गहराता जा रहा है। जब जान चली जाती है, तब भी जिम्मेदारी तय करने की बजाय मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

यह मान लेना कि दूषित पानी की आपूर्ति केवल अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है, आधा सच होगा। वास्तव में इस अनदेखी में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक तंत्र के हर स्तर की भूमिका है। पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री सभी अपने-अपने दायरे में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अक्सर उनकी प्राथमिकता चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने तक सीमित रह जाती है। बिजली, पानी, सीवर और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं चुनावी भाषणों में जरूर शामिल होती हैं, लेकिन धरातल पर इनके क्रियान्वयन की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। नगर निकायों के अधिकारी और कर्मचारी भी इसी मानसिकता के साथ काम करते हैं, जिसमें न्यूनतम काम चलाऊ व्यवस्था को ही पर्याप्त मान लिया जाता है।

पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की गुणवत्ता पर ध्यान न दिया जाना किसी भी समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वच्छ पेयजल केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा प्रश्न है। जब किसी देश में करोड़ों लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को विवश हों, तो यह उस देश की विकास गाथा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बीमार पड़ते हैं, उनकी आय का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च होता है और उनकी जीवन गुणवत्ता लगातार गिरती जाती है।

पेयजल की गुणवत्ता में सुधार इसलिए भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जांच और निगरानी का काम ईमानदारी से नहीं किया जाता। जल शुद्धिकरण संयंत्रों, पाइपलाइनों और जल स्रोतों की नियमित जांच कागजों में तो होती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग होती है। कई बार पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट पहले से तय कर ली जाती है और वास्तविक स्थिति को छुपा लिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि समस्या भीतर ही भीतर बढ़ती रहती है और एक दिन अचानक किसी बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने आती है।

दूषित पानी की समस्या का एक और गंभीर पहलू यह है कि लोगों को स्वच्छ पानी पाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं या फिर घरों में महंगे आरओ और फिल्टर लगवाने पड़ते हैं। यह स्थिति असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि जो लोग यह खर्च वहन नहीं कर सकते, वे दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। इस तरह पानी भी धीरे-धीरे एक ऐसी वस्तु बनता जा रहा है, जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। शहरी इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति का एक बड़ा कारण अनियोजित विकास है। देश के अधिकांश शहरों में बड़ी संख्या में ऐसी कॉलोनियां हैं, जो बिना किसी समुचित योजना के बसाई गईं। बाद में राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें नियमित तो कर दिया गया, लेकिन आवश्यक बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया गया। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस इलाके को नियोजित घोषित कर दिया गया, लेकिन यह नहीं देखा गया कि यहां सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन का नेटवर्क किस तरह बनाया गया है।

अभियान

जब काशी नरेश ने राजसत्ता, वैभव और संबंधों से ऊपर उठकर दिया धर्म और करुणा का सर्वोच्च संदेश

माघ महीने की कंपकंपा देने वाली ठंड ने काशी की प्राचीन गलियों को जैसे जकड़ लिया था। गंगा और वरुणा के संगम पर बसी यह सनातन नगरी, जहाँ सामान्य दिनों में जीवन की धारा कभी नहीं थमती, उस सुबह असामान्य रूप से शांत और स्थिर प्रतीत हो रही थी। उत्तर दिशा से आती बर्फीली हवाएँ हड्डियों में उतर रही थीं। कोहरे की मोटी परत ने सूर्य की किरणों को भी बाँध लिया था। साधु-संत अपने कमंडल समेटे झोपड़ियों में दुबके थे, मल्लाह नावें किनारे बाँधकर आग के सहारे बैठे थे और गरीब जन अपने फटे-पुराने वस्त्रों में किसी तरह ठंड से लड़ रहे थे। यह वही काशी थी, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों समान भाव से स्वीकार किए जाते हैं, पर उस दिन ठंड ने जीवन को थाम सा लिया था।

इसी ठिठुरती सुबह काशी नरेश की रानी करुणा अपने दास-दासियों और अंगरक्षकों के साथ वरुणा नदी के तट पर स्नान के लिए पहुँचीं। राजमहल के सुरक्षित और गरम वातावरण में पली रानी के लिए यह ठंड केवल एक क्षणिक असुविधा थी, जीवन का संघर्ष नहीं। जैसे ही उन्होंने नदी के शीतल जल में चरण रखा, तीखी सर्द लहर उनके शरीर में समा गई। कुछ ही पलों में हाथ-पाँव सुन्न होने लगे, दाँत कँपकँपाने लगे और श्वास की गति असामान्य हो गई। दासियाँ घबरा उठीं। उन्होंने चारों ओर देखा, पर जलाने योग्य सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिली। जो लकड़ियाँ थीं, वे ओस और कोहरे से भीगी हुई थीं और जलने की स्थिति में नहीं थीं। ठंड से व्याकुल रानी की दृष्टि नदी किनारे बनी झोपड़ियों पर जा टिकी। वे झोपड़ियाँ गरीबों, मल्लाहों और साधुओं का एकमात्र आश्रय थीं। संयोगवश उस समय वे लोग कहीं गए हुए थे और झोपड़ियाँ खाली पड़ी थीं। रानी के मन में उस क्षण यह विचार नहीं आया कि यही झोपड़ियाँ किसी के जीवन की सारी पूँजी हैं, किसी के बच्चों की छत हैं, किसी बुज़ुर्ग की आख़िरी शरण हैं। उन्होंने अधीर स्वर में एक दासी को आदेश दिया कि किसी एक झोपड़ी में आग लगा दी जाए, ताकि वे अपने शरीर को ताप दे सकें। आदेश का पालन हुआ, लेकिन प्रकृति ने मानो चेतावनी देने का अवसर भी नहीं दिया। तेज़ और शुष्क हवा ने आग को पल भर में भड़का दिया। एक झोपड़ी से उठी लपटें दूसरी में कूद पड़ीं। सूखी घास और फूस ने आग को और विकराल बना दिया। देखते ही देखते पूरी बस्ती आग की चपेट में आ गई। धुएँ के काले बादल आकाश में उठने लगे। कुछ ही क्षणों में वह स्थान, जहाँ थोड़ी देर पहले जीवन की सादगी बसती थी, राख और अंगारों में बदल गया। रानी को ठंड से राहत मिल गई, पर उनके एक निर्णय ने कई परिवारों को जीवन भर का दुःख दे दिया।

जब वे गरीब लौटे तो उनकी आँखों के सामने केवल जली हुई झोपड़ियाँ, राख में बदले बर्तन और बुझी हुई चूल्हें थीं। बच्चों की चीखें और स्त्रियों का विलाप गंगा की लहरों में घुल गया। यह केवल संपत्ति का नुकसान नहीं था, यह सम्मान, सुरक्षा और आश्रय का विनाश था। विवश होकर वे लोग न्याय की गुहार लेकर राजदरबार पहुँचे। फटे वस्त्र, जले हुए बर्तन और आँसुओं से भरी आँखों के साथ वे महाराज के सामने खड़े हुए। उनका करुण विलाप पूरे दरबार को स्तब्ध कर रहा था।

काशी नरेश ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनका हृदय व्यथा से भर उठा। वे भीतर गए और रानी से इस घटना के विषय में प्रश्न किया। रानी ने सहज और लगभग उदासीन भाव से कहा कि वे तो केवल घास-फूस की झोपड़ियाँ थीं, उनके जल जाने से कोई बड़ा अनर्थ नहीं हुआ। यह उत्तर सुनते ही महाराज के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह केवल भूल नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार और संवेदनहीनता का परिणाम है।

उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया। बिना किसी विलंब के आदेश दिया गया कि रानी के रेशमी वस्त्र और आभूषण उतार लिए जाएँ। उनके शरीर से वैभव का हर चिह्न हटा दिया गया और उन्हें साधारण, फटे-पुराने वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद रानी को उसी अवस्था में राजसभा में लाया गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। प्रजा, मंत्री और दरबारी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। यह दृश्य किसी अपमान का नहीं, बल्कि न्याय की तैयारी का संकेत था।

न्यायासन पर बैठे काशी नरेश ने दृढ़ और स्थिर स्वर में घोषणा की कि रानी करुणा को तत्काल राजमहल से निष्कासित किया जाता है। जिन झोपड़ियों को उनके आदेश से जलाया गया, उन्हें वही अपने हाथों से भिक्षा माँगकर पुनः बनवाएँगी। जब तक उन गरीबों के सिर पर छत नहीं आ जाती और उनका जीवन फिर से सामान्य नहीं हो जाता, तब तक रानी को महल में लौटने की अनुमति नहीं होगी। यह दंड प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि अनुभव और प्रायश्चित का मार्ग था।

सभा में जयघोष गूँज उठा। यह जय किसी व्यक्ति के अपमान की नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की विजय की थी। रानी की आँखों से आँसू बहने लगे। उसी क्षण उनका अहंकार टूट गया। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि सत्ता और वैभव का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उन्होंने समझा कि करुणा केवल नाम नहीं, आचरण है, और न्याय केवल शब्द नहीं, त्याग है।

कहा जाता है कि रानी ने महीनों तक भिक्षा माँगकर उन झोपड़ियों का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने भूख, अपमान और पीड़ा का अनुभव किया, जिसे वे पहले कभी समझ नहीं पाई थीं। जब अंततः गरीबों की बस्ती फिर से बस गई और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटी, तब महाराज ने रानी को महल लौटने की अनुमति दी। उस दिन रानी केवल राजमहल में नहीं लौटीं, बल्कि एक नई चेतना और संवेदनशील हृदय के साथ लौटीं। काशी के इतिहास में यह घटना "मोह से मुक्त न्याय" के नाम से अमर हो गई। यह कथा आज भी यह सिखाती है कि सच्चा न्याय वही है, जो अपने और अपनों के मोह से ऊपर उठकर दिया जाए। जहाँ सत्ता करुणा से जुड़ती है, वहीं राजधर्म जीवित रहता है। यह प्रसंग केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं, बल्कि हर युग के शासकों, न्यायाधीशों और समाज के लिए एक शाश्वत संदेश है कि अधिकार तभी पवित्र है, जब वह दायित्व और संवेदना से बंधा हो।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कोटडासांगानी को मिला आधुनिक स्वास्थ्य का नया आधार, 3.61 करोड़ की लागत से बने रेफरल अस्पताल ने बदली क्षेत्र की उम्मीदें

(जीएनएस)। राजकोट जिले के कोटडासांगानी तालुका के लिए यह दिन स्वास्थ्य सुविधाओं के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब 3.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ सांसद परसोत्तमभाई रूपाला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी और स्थानीय विधायक श्रीमती भानुबेन बाबरिया विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, कर्मचारी और क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह अस्पताल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि लोगों की वर्षों पुरानी अपेक्षाओं का साकार रूप है।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद परसोत्तमभाई रूपाला ने कहा कि गुजरात सरकार नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह स्पष्ट नीति रही है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जाएं, जहां लोगों को प्राथमिक ही नहीं, बल्कि रेफरल स्तर की सुविधाएं भी मिल सकें। उन्होंने स्मरण कराया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसने दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के समय अनगिनत जिंदगियों को बचाया। उसी सोच की निरंतरता में आज आयुष्मान भारत योजना जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना देशवासियों को मिली है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी साबित हो रही है।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने को विकास का केंद्र बनाया। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोटडासांगानी जैसे तालुका में रेफरल अस्पताल की स्थापना से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा, बल्कि आसपास के गांवों की आबादी को भी बेहतर उपचार के लिए दूर शहरों की ओर नहीं भटकना पड़ेगा।

विधायक श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह भागीदारी और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ से बचा जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि यह नया स्वास्थ्य केंद्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करेगा।

उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने रिबन काटकर और शिलापट्ट का अनावरण कर अस्पताल को जनता को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि पहले यहां संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत करते हुए 3.61 करोड़ रुपये की लागत से इस रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे आधुनिक चिकित्सा मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है।

इस नए स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तरों वाला पुरुष एवं महिला वार्ड, आधुनिक लेबोरेटरी, एक्स-रे विभाग, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी विभाग, लेबर रूम, सोनोग्राफी कक्ष, एएनसी रूम, टीबी विभाग, ड्रेसिंग रूम और जनरल ओपीडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विशेष रूप से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन और सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई, जिसके बाद अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। क्वालिटी मैनेजिंग डायरेक्टर पी. के. सिंह ने मौखिक स्वागत भाषण दिया और अस्पताल की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। लीडिंग किशोर सिंह जडेजा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन सीआरसी को-ऑर्डिनेटर सुरेशभाई आंबलिया ने किया। इस अवसर पर हेल्थ कमिटी की चेयरमैन श्रीमती लीलावंतीबेन ठुमर, मार्केट यार्ड के चेयरमैन एन. डी. जडेजा, पूर्व विधायक लाखाभाई सागठिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अस्पताल स्टाफ और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कोटडासांगानी में इस रेफरल अस्पताल का उद्घाटन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह अस्पताल आने वाले समय में क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए भरोसे का केंद्र बनेगा और "इलाज के लिए शहर" की मजबूरी को काफी हद तक समाप्त करेगा।

राइसिन जहर से दहशत फैलाने की साजिश अब एनआईए करेगी देशव्यापी जांच

(जीएनएस)। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही राइसिन जहर आधारित आतंकी साजिश की जांच अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के हाथों में सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) से लेकर एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला इस साजिश की अंतरराष्ट्रीय कड़ियों, आतंकी संगठनों से जुड़े संपर्कों और संभावित बड़े हमले की आशंका को देखते हुए लिया गया है।

गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज इस संवेदनशील मामले को एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। अब एनआईए इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी और यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था और इसके पीछे कौन-कौन से आतंकी संगठन या विदेशी ताकतें सक्रिय थीं।

गौरतलब है कि गुजरात एटीएस ने पिछले साल 9 नवंबर को इस साजिश का भंडाफोड़ करते हुए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया

था। गिरफ्तार आरोपियों में हैदराबाद के मूल निवासी डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम शामिल हैं। इन तीनों पर हथियारों और रसायनों की मदद से बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। एटीएस ने इनके खिलाफ यूएपीए के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान सामने आया था कि डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद को 7 नवंबर को गांधीनगर के अडालज इलाके के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से दो अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और चार लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया था। यह बरामदगी अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि अरंडी के तेल से राइसिन नामक अत्यंत घातक जहर तैयार किया जा सकता है। राइसिन को दुनिया के सबसे खतरनाक विषैले पदार्थों में गिना जाता है और इसकी बेहद कम मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है।

एटीएस की शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि डॉ. सैयद चीन से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर चुका है और उसे रसायन विज्ञान तथा मेडिकल ज्ञान का अच्छा खासा अनुभव है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल वह आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार, वह राइसिन जहर तैयार करने के लिए आवश्यक शोध कर चुका था, उसने उपकरण और कच्चा माल जुटा लिया था और प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अगर समय रहते उसे नहीं रोका जाता, तो यह साजिश बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान का कारण बन सकती थी।

इस मामले में उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी बनासकांठा जिले से हुई थी। दोनों पर आरोप है कि वे डॉ. सैयद को अवैध हथियार पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने पहले ही यह पुष्टि की थी कि डॉ. सैयद का हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला है और वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डॉ. सैयद के पाकिस्तान में मौजूद कई व्यक्तियों से संपर्क में होने की भी जानकारी सामने आई थी। इन तथ्यों ने जांच एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी थी, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि भारत के भीतर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश विदेशी सरपरस्ती में रची जा रही थी।

राइसिन जैसे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल पारंपरिक बम या गोलीबारी से अलग और कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है। यह एक ऐसा जहर है, जिसकी पहचान करना मुश्किल होता है और जिसके इस्तेमाल से दहशत का माहौल पैदा किया जा सकता है। इसी वजह से इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

नए वर्ष की पहली किरण के साथ अनुशासन, सेवा और स्वास्थ्य का संकल्प, सूरत होमगार्ड्स ने सामूहिक सूर्य नमस्कार से दिया सकारात्मक संदेश

(जीएनएस)। नए वर्ष के शुभारंभ को अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी बनाने के उद्देश्य से सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा "नए वर्ष की प्रथम सूर्य किरण को नमस्कार" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक योग कार्यक्रम नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा भावना और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधिकारी (पुलिस रिफॉर्म्स), कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स पियूष पटेल तथा सीनियर स्टाफ ऑफिसर मुख्यालय मनीष त्रिवेदी के मार्गदर्शन में, गुजरात राज्य योग बोर्ड, गुजरात सरकार के अनुरोध पर पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत सूरत शहर में भी व्यापक सहभागिता देखने को मिली। सूरत शहर के जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया के नेतृत्व में शहर की सभी ज़ोन और यूनिटों में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातःकाल वातावरण में जब नए वर्ष की पहली सूर्य किरण धरती पर उतरी, उसी क्षण सूर्य प्रार्थना और संगठन मंत्र के पाठ के साथ कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की गई। अनुशासनबद्ध पंक्तियों में खड़े होमगार्ड्स का समवेत स्वर और समन्वित योग अभ्यास पूरे वातावरण को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर रहा था। यह दृश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक एकाग्रता और सामूहिक एकता का भी सशक्त उदाहरण बन गया।

कार्यक्रम में सूरत शहर की विभिन्न ज़ोन एवं यूनिटों से बड़ी संख्या में होमगार्ड्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ए ज़ोन से 123, बी ज़ोन से 145, सी ज़ोन से 231, डी ज़ोन से 107, रांदेर यूनिट से 154, सचिन यूनिट से 156 तथा महिला यूनिट से 120 महिला होमगार्ड्स ने सहभागिता की। इस प्रकार कुल 1432 होमगार्ड्स ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर नए वर्ष का स्वागत किया। महिला यूनिट की ओर से स्टाफ ऑफिसर (महिला) धर्मिष्ठा मानकिया की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरक बनाया, वहीं विभिन्न ज़ोन के ऑफिसर कमांडिंग द्वारा अपने-अपने यूनिटों का नेतृत्व अनुशासन और समर्पण के साथ किया गया।

इस अवसर पर जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया ने सूर्य नमस्कार के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार केवल एक योग क्रिया नहीं, बल्कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। यह शरीर को भीतर से शुद्ध करता है, रक्त परिसंचरण को सुदृढ़ बनाता है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स जैसे अनुशासित बल के लिए शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है, और सूर्य नमस्कार दोनों को सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

कार्यक्रम के दौरान सभी होमगार्ड्स ने हाथ जोड़कर 'स्वदेशी और संस्कृति' के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। यह संकल्प न केवल स्वास्थ्य, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग परंपरा और आत्मनिर्भरता के विचार को जन-जन तक पहुंचाने की भावना को भी दर्शाता है। सूरत पुलिस सलाहकार समिति के सदस्य रमेशभाई दुधात, अनिलभाई सोजित्रा, हितेशभाई लाठिया एवं राजूभाई सूर्यदर्शनी ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का अभिनंदन किया और होमगार्ड्स के इस प्रयास की सराहना की। संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय सेकंड कमांडेंट प्रणव ठाकर तथा योग बोर्ड सूरत जिला को-ऑर्डिनेटर नवनीत शेलडिया द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कृति बारडोलिया, भीमभाई बासेल, श्वेता लिंबाचिया, निमिषा शाह, अनीता चापनेरी, कोमल गज्जर, चैताली चौहान, राकेश मेहता, धर्मिष्ठा मेहता, हिना चावड़ा, संध्या पटेल एवं मयूरी मिस्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम की सफलता पर निरीक्षक-प्रशिक्षक जयदीप कातरिया ने गुजरात स्टेट योग बोर्ड, पत्रकार मित्रों तथा उपस्थित सभी जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कुल मिलाकर, सूरत होमगार्ड्स द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नए वर्ष की शुरुआत को स्वास्थ्य, अनुशासन और सेवा भावना के साथ जोड़ने का एक प्रेरणादायी प्रयास साबित हुआ, जिसने यह संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच के साथ ही समाज और राष्ट्र की सच्ची सेवा संभव है।

साबरमती-खोडियार के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ़ रोड फाटक) 05 जनवरी 2026 को रात्रि 00.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक तथा दोपहर 15.00 बजे से सायं 18.00 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा।

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अहमदाबाद द्वारा ऑटो चालकों पर बड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं निर्धारित मानकों से अधिक किराया वसूलने संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 04.01.2025 को रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद द्वारा विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 6 ऑटो चालकों के ऑटो जप्त किए गए तथा संबंधित ऑटो चालकों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के

प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद यात्रियों की सुरक्षा, सम्मान एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भविष्य में भी यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या अनियमितता न हो, इसके लिए ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

दीन सहायक विद्या मंदिर बमरोली में बच्चों की मुस्कान और उत्साह से सजा आनंद मेला, निःशुल्क शिक्षा केंद्र में उमड़ा उल्लास

(जीएनएस)। सूरत के बमरोली क्षेत्र में स्थित हिन्दू सनातन पब्लिक सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित दीन सहायक विद्या मंदिर निःशुल्क शिक्षा केंद्र में रविवार, 4 जनवरी 2026 को बच्चों के लिए आनंद मेला एवं फन फेयर का भव्य और उल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों की खुशियों, रंग-बिरंगे स्टॉलों और उमंग से भरा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संस्थापक पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई, जिसके बाद विधिवत रूप से आनंद मेले का शुभारंभ हुआ।

आनंद मेले में विद्यालय के बच्चों ने अपने-अपने घरों से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लाकर स्वयं के स्टॉल लगाए। बच्चों ने न केवल भोजन बनाया, बल्कि उसकी साज-सज्जा, बिक्री और ग्राहकों से संवाद की जिम्मेदारी भी पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ निभाई। मेले में पानीपुरी, भेलपुरी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, आलू पूरी, चाय, कॉफी, दूध, पकोड़ा, समोसा, जलेबी, लड्डू, खमन, पॉपकॉर्न, पास्ता और पावभाजी जैसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। स्टॉलों पर खरीदारी करने के लिए बच्चों, अभिभावकों और आगंतुकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरे परिसर में मेले जैसा जीवंत वातावरण बन गया।

इस आयोजन में स्टॉल लगाने वाले बच्चों में अंशिका, अनामिका, नितेश, आदर्श, साक्षी, अंश, रागिनी, सिद्धि, अयांश, कनक मोदी और अनुष्का सहित कई छात्र-छात्राएं शामिल रहीं। सभी बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने-अपने स्टॉल संभाले और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेहनत और रचनात्मकता का परिचय दिया। बच्चों का उत्साह, मुस्कान और आपसी सहयोग पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रहा। पूरे आयोजन का सफल संचालन शिक्षक आदित्य यादव एवं आरती विश्वकर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने बच्चों को हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया।

संस्था के प्रमुख पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को केवल मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि आनंद मेला जैसे कार्यक्रम बच्चों को व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र, धन प्रबंधन, मेहनत की कीमत और संसाधनों के सही उपयोग की समझ प्रदान करते हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले इन नन्हे-मुन्ने बच्चों की सक्रिय सहभागिता और लगन यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर हर बच्चा आगे बढ़ सकता है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। अभिभावकों और उपस्थित अतिथियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दीन सहायक विद्या मंदिर में आयोजित यह आनंद मेला न केवल एक मनोरंजक कार्यक्रम रहा, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल को निखारने की दिशा में एक प्रेरणादायक और यादगार पहल बनकर उभरा।

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर में जलजन्य टायफाइड की स्थिति को लेकर प्रशासन को युद्धस्तर पर कार्यवाही के आदेश दिए

- श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए
- श्री अमित शाह ने मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए
- श्री अमित शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के फैलाव को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन की सघन जांच के आदेश दिए

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 तथा आदिवाडा क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण दूषित पानी से बच्चों एवं नागरिकों में टायफाइड के मामले सामने आए हैं। इस संदर्भ में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ निरंतर संपर्क में रहकर चर्चा की, वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही करने के सुझाव दिए हैं।

श्री अमित शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर टायफाइड से प्रभावित बच्चों एवं नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, साथ ही गांधीनगर सिविल अस्पताल में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का और फैलाव न हो, इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पाइप लाइन की सघन जांच करने के आदेश दिए हैं।

गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड मामलों को लेकर सघन स्वास्थ्य व्यवस्था

एवं सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की गई है। जिन क्षेत्रों से ये संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उन सेक्टर 24, 26 और 28 तथा आदिवाडा क्षेत्रों में 75 हेल्थ टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

अब तक संदिग्ध टायफाइड के 113 मामले सामने आए हैं, जिनमें से उपचाराधीन मरीजों में से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 94 मरीजों को गांधीनगर सिविल अस्पताल तथा सेक्टर 24 और 29 के यूएचसी में उपचार दिया जा रहा है तथा सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रभावित क्षेत्रों में 24×7 ओपीडी शुरू की गई है। जिन मरीजों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।

गांधीनगर महानगर पालिका की सर्वेक्षण टीमों द्वारा अब तक 20,800 से अधिक घरों का सर्वे कर 90 हजार से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया है। रोग रोकथाम के उपायों के अंतर्गत 30 हजार क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस पैकेट का वितरण किया गया है।

सर्वेक्षण टीमें घर-घर जाकर जागरूकता पत्रिकाओं का वितरण कर रही हैं तथा लोगों को पानी उबालकर पीने, बाहर का खाना न खाने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी जानकारियां प्रदान कर रही हैं।

रोग नियंत्रण के लिए पानी के सुपर क्लोरीनेशन की कार्यवाही को तेज किया गया है और पानी में क्लोरीन की मात्रा की नियमित जांच की जा रही है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार तक 24×7 जलापूर्ति के स्विच ओवर की कार्यवाही की जाएगी।

इसके परिणामस्वरूप सुदूरवर्ती घरों तक भी उचित मात्रा में क्लोरीनयुक्त पानी पहुंचाया जा सकेगा।

रोग प्रभावित क्षेत्रों में जहां छोटे-बड़े लीकेज पाए गए हैं, उनकी मरम्मत भी तत्काल प्रभाव से की जा रही है।

महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में पानीपुरी, रगड़ा पैटीस, बर्फ के गोले, शिकंजी सोडा तथा दूध से बने पेय पदार्थों की बिक्री की भी सघन जांच की जा रही है।

सूरत सहित दक्षिण गुजरात में कड़ाके की ठंड का असर गहराया लगातार गिरते तापमान ने बदली जनजीवन की रफ्तार

(जीएनएस)। सूरत समेत पूरे दक्षिण गुजरात में सर्दी ने अब पूरी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। बीते कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह-सुबह और देर रात ठंड का तीखा अहसास होने लगा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर साफ नजर आ रहा है। हल्की ठंड के दौर से निकलकर अब मौसम ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां लोगों को गर्म कपड़ों के सहारे ही बाहर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर सुबह के समय कुहासे जैसी ठंडक और रात के वक्त ठंडी हवाओं ने सूरतवासियों को यह एहसास करा दिया है कि इस बार सर्दी देर से सही, लेकिन पूरे असर के साथ आई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सूरत शहर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 15.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में यह क्रमिक लेकिन लगातार गिरावट खासतौर पर रात के समय ज्यादा महसूस की जा रही है। जैसे-जैसे सूरज ढलता है, ठंड तेजी से बढ़ती जाती है और देर रात तक सर्द हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती हैं।

फिलहाल सूरत शहर में उत्तर दिशा से

करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब दक्षिण गुजरात तक पहुंच रहा है। वहां से आने वाली ठंडी हवाएं वातावरण की नमी के साथ मिलकर ठंड को और अधिक तीव्र बना रही हैं। हवा की दिशा और मौजूदा मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ठंड का यह सिलसिला बना रहेगा और तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद राहत मिलने की संभावना कम है। ठंड बढ़ने के साथ ही सूरत के बाजारों और सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है। लोग सुबह की सैर पर निकलते समय स्वेटर, जैकेट और शॉल में लिपटे नजर आ रहे हैं। दफ्तर और कारखानों में काम पर जल्दी निकलने वाले कर्मचारियों के लिए गर्म कपड़े अब अनिवार्य हो गए हैं। वहीं, रात के समय फुटपाथों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते या हीटर का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। ठंड के कारण देर रात तक चहल-पहल रहने वाले कई इलाकों में भी अब अपेक्षाकृत सन्नाटा पसरा रहने लगा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक सूरत और दक्षिण गुजरात में ठंड का यही दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है, जिससे साफ है कि फिलहाल सर्दी से राहत के आसार नहीं हैं। ऐसे में डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने पर जोर दिया जा रहा है।

चुनावी समर से पहले तमिलनाडु में डीएमके का तेज़ राजनीतिक आक्रमण चार दिनों में घोषणाओं की झड़ी से स्टालिन ने बनाया बढ़त का माहौल

(जीएनएस)। नए वर्ष 2026 की दस्तक के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में रंगती दिखाई देने लगी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और मुख्य विपक्षी अन्नाद्रमुक के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महज चार दिनों के भीतर तीन बड़ी और असरदार घोषणाएं कर यह संकेत दे दिया है कि डीएमके अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और किसी भी मोर्चे पर विपक्ष को बढ़त लेने का मौका देने के मूड में नहीं है। इन घोषणाओं को केवल प्रशासनिक फैसलों के रूप में नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई इस बार पहले से अधिक दिलचस्प मानी जा रही है। जहां डीएमके अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों और लोकलुभावन फैसलों के सहारे सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, वहीं एआईएडीएमके लगातार सरकार पर हमलावर रुख अपनाकर वापसी की जमीन तलाश रही है। इस सियासी समीकरण को और जटिल बना दिया है अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम ने। विजय की लोकप्रियता और युवाओं में उनकी पकड़ ने दोनों प्रमुख दलों की रणनीतियों पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में डीएमके नेतृत्व यह भली-भांति समझता है कि किसी भी तरह की ढिलाई चुनावी नुकसान में बदल सकती है।

इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री स्टालिन ने लगातार घोषणाएं कर न केवल सरकार की सक्रियता दिखाई, बल्कि विभिन्न वर्गों को सीधे संदेश भी दिया। 3 जनवरी को तमिलनाडु एग्रेरियन पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह भर दिया। लंबे समय से पेंशन को लेकर असंतोष जता रहे कर्मचारी संगठनों के लिए यह फैसला

बड़ी राहत साबित हुआ। खास तौर पर जैक्टो-जियो जैसे प्रभावशाली संगठनों ने इस घोषणा के बाद प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिससे सरकार को एक बड़े राजनीतिक संकट से राहत मिली। यह फैसला चुनाव से पहले कर्मचारियों के नाराजगी के मुद्दे को काफी हद तक शांत करने में सफल माना जा रहा है।

इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने पोंगल पर्व के अवसर पर 22 लाख राशन कार्डधारकों को 3000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा कर आम जनता को साधने का प्रयास किया। पहले सरकार की ओर से पोंगल उपहार के रूप में खाद्यान्न और गन्ना देने की योजना सामने आई थी, लेकिन नकद सहायता जोड़ने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों और निम्न आय वर्ग के परिवारों में इस फैसले को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। डीएमके का यह कदम यह दर्शाता है कि पार्टी चुनाव से पहले सीधे-सीधे आर्थिक राहत के जरिए मतदाताओं के बीच भरोसा मजबूत करना चाहती है।

इसके बाद 5 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा 20 लाख कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना का शुभारंभ एक और बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आया। पहले चरण में 10 लाख छात्रों को लैपटॉप देने की योजना है, जिसमें सरकारी इंजीनियरिंग, कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, विधि, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों के छात्र शामिल हैं। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण के नाम पर यह घोषणा खास तौर पर युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित करने वाली मानी जा रही है। डेल, एसर और एचपी जैसी नामी कंपनियों के उपकरण शामिल किए जाने से योजना की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर भी सकारात्मक धारणा बनी है।

इन तीनों घोषणाओं को यदि एक साथ देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि डीएमके ने कर्मचारियों, गरीब परिवारों और युवाओं—तीनों बड़े वोट बैंक को एक साथ साधने की कोशिश की है। चुनावी राजनीति में यह संतुलन बेहद अहम माना जाता है। सरकार का यह भी दावा है कि माध्यमिक शिक्षकों की लंबित मांगों का समाधान भी जल्द निकाला जाएगा, ताकि चुनाव से पहले किसी बड़े वर्ग में असंतोष न पनप सके। नर्सों की हड़ताल पहले ही समाप्त हो चुकी है, जिसे डीएमके अपनी प्रशासनिक सफलता के रूप में पेश कर रही है।

इधर विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं है। एआईएडीएमके ने अपने घोषणापत्र की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने राज्यभर में दौरे कर विभिन्न वर्गों की मांगें सुनने का ऐलान किया है। वहीं डीएमके ने सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में घोषणापत्र समिति बनाकर जनता से सुझाव लेने के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। यह दिखाता है कि दोनों दल आधुनिक तकनीक और जमीनी संपर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस समय तेज़ रफ्तार से चुनावी दिशा में बढ़ रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन की हालिया घोषणाओं ने डीएमके को शुरुआती बढ़त जरूर दिलाई है, लेकिन चुनावी रण में अंतिम फैसला जनता के मूड और आने वाले महीनों की सियासी चालों पर निर्भर करेगा। इतना तय है कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या बरकरार रहने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मुकाबला साबित होगा।

मनरेगा की 'आत्मा' पर सियासी संग्राम, कानून बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़क से संसद तक उतरेगी, 10 जनवरी से देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ संग्राम'

(जीएनएस)। मुंबई। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों की आजीविका और रोजगार के लिए विशेष महत्व रखने वाला मनरेगा कानून, जिसे सरकार ने हाल ही में VB-G RAM G के नाम से नया रूप दिया है, इस समय राजनीतिक बहस और आंदोलन का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने इसे केवल नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों के अधिकार पर सीधा हमला बताया है और 10 जनवरी से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ सिम्बॉलिक नहीं होगा, बल्कि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक इसका विस्तार किया जाएगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि नए VB-G RAM G कानून में मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया गया है। पार्टी का कहना है कि इससे काम का अधिकार अब कानूनी हक नहीं रह जाएगा और इसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर जो आदर्श स्थापित किया गया था, वह भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि मनरेगा गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी देता है, जबकि नए कानून के प्रावधानों में यह गारंटी समाप्त हो जाती है और सरकार की मंशा इसे सिर्फ एक प्रशासनिक योजना में बदलने की है।

इस आंदोलन की निगरानी और रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने अजय माकन की अध्यक्षता में नौ नेताओं की एक समन्वय समिति गठित की है। समिति में जयराम रमेश, संदीप दीक्षित, उदित राज, प्रियांक खरगे, डी. अनसूया सीताक्का, दीपिका पांडेय सिंह, सुनील पवार और

मनीष शर्मा शामिल हैं। समिति का काम देशभर में आंदोलन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करना, ग्रामीण जनता के बीच कानून के प्रभाव को समझाना और सरकार पर दबाव बनाना होगा। समिति तय करेगी कि पंचायत स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस किस तरह से आंदोलन को प्रभावी बनाए।

कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा का इतिहास ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा है। कोरोना महामारी और अन्य आर्थिक संकट के समय मनरेगा ने लाखों परिवारों की आजीविका बचाई थी। इसी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की गई। नए कानून में नाम परिवर्तन और अन्य बदलावों को कांग्रेस गरीब विरोधी करार दे रही है और इसे ग्रामीण भारत में सरकार की उदासीन नीति का उदाहरण बता रही है।

सरकार के अनुसार, VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) कानून का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और गांवों में रोजगार के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन होंगे।

लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस कानून में मनरेगा की अधिकार आधारित संरचना को बदलकर इसे सिर्फ प्रशासनिक योजना में बदल दिया गया है। नए कानून के तहत अब ग्रामीणों को रोजगार का कानूनी हक नहीं मिलेगा और यह योजना सिर्फ सरकारी निर्णयों पर निर्भर हो जाएगी। इससे विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी की सोच और योजना पर हमला भी बताया है, क्योंकि मूल मनरेगा गांधीवादी दृष्टिकोण से गरीबों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था।

'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरण के माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि नए कानून से उनके रोजगार और आजीविका पर क्या असर पड़ेगा। पार्टी ने साफ किया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से होगा, लेकिन इसका दायरा व्यापक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के बदलाव पर राजनीतिक बहस और आंदोलन से ग्रामीण भारत में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, यह आंदोलन केंद्र सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह सीधे गरीब और ग्रामीण वर्ग के हितों से जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि कानून के विरोध में कांग्रेस का अभियान ग्रामीण मतदाताओं के बीच उसकी पहचान को मजबूत कर सकता है।

मनरेगा कानून का नाम बदलना और इसके ढांचे में बदलाव केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। यह सीधे ग्रामीण भारत के गरीबों के अधिकार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान से स्पष्ट है कि वह इस बदलाव के खिलाफ लगातार संघर्ष करेगी। 10 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन का असर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी दिखाई देगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण भारत में जनता के बीच कानून के प्रभाव को समझाना और सरकार पर दबाव बनाना कांग्रेस की प्राथमिक रणनीति होगी, जो आने वाले महीनों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तृत संस्करण में बदलकर इसे लगभग 1200-1300 शब्दों का लंबा, अखबार-लेख शैली का रिपोर्ट तैयार कर दूँ, जिसमें पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक विश्लेषण और आगामी आंदोलन की रणनीति सब शामिल हो। क्या मैं ऐसा कर दूँ?

नए वर्ष की सुस्त शुरुआत के बीच प्राथमिक बाजार में सीमित हलचल, तीन एसएमई कंपनियां आजमाएंगी निवेशकों का भरोसा

(जीएनएस)। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के प्राथमिक शेयर बाजार में अपेक्षाकृत धीमी गतिविधि देखने को मिल रही है। नए साल के पहले सप्ताह में आईपीओ बाजार में जोश की जगह सतर्कता का माहौल बना हुआ है। निवेशकों और कंपनियों दोनों की ओर से फिलहाल इंतजार और आकलन की रणनीति अपनाई जा रही है। जनवरी के पहले सप्ताह में मेनबोर्ड से जहां केवल एक आईपीओ आने की संभावना है, वहीं एसएमई सेगमेंट की तीन कंपनियां ही बाजार में उतरकर अपनी किस्मत आजमाएंगी। बाजार विश्लेषक इसे साल के शुरुआती दिनों में निवेशकों की स्वाभाविक सावधानी और वैश्विक तथा घरेलू संकेतों को समझने की प्रवृत्ति से जोड़कर देख रहे हैं। आमतौर पर नया साल शुरू होते ही निवेशक पिछले वर्ष के बाजार रुझानों, कॉरपोरेट नतीजों और आर्थिक संकेतकों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। वर्षांत की छुट्टियों के बाद बाजार में लौटने वाले निवेशक जल्दबाजी के बजाय संतुलित कदम उठाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में आईपीओ गतिविधियां अक्सर सीमित रहती हैं। इस वर्ष भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। कंपनियां भी इस समय निवेशक धारणा को परखने के मूड में नजर आ रही हैं और बड़े इश्यू लाने से पहले बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार कर रही हैं।

हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुस्ती को नकारात्मक संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मजबूत घरेलू तरलता, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल निवेशकों की निरंतर भागीदारी तथा अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती आने वाले महीनों में प्राथमिक बाजार को फिर से गति दे सकती है। चालू तिमाही के आगे बढ़ने के साथ ही कई बड़े और चर्चित आईपीओ बाजार में दस्तक दे सकते हैं, जिससे निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

इसी सीमित लेकिन अहम गतिविधि के बीच एसएमई श्रेणी में वर्ष 2026 का पहला आईपीओ गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया का होगा। यह इश्यू 6 जनवरी से 8 जनवरी तक खुला रहेगा। कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से करीब 29 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिससे कंपनी अपने परिचालन को और सुदृढ़ बना सके। गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया का यह आईपीओ बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा, जहां छोटे और मध्यम निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है।

इसके बाद विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल भी पूंजी बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच फिक्स्ड प्राइस आईपीओ के जरिए लगभग 35 करोड़ रुपये जुटाएगी। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सक्रिय है और इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया तथा ई-रिक्शा जैसे वाहनों का निर्माण और विपणन करती है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के बीच इस क्षेत्र की कंपनियों पर निवेशकों की विशेष नजर रहती है। यह इश्यू एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा।

इसी अवधि में यजूर फाइबर्स का आईपीओ भी बाजार में आने जा रहा है, जिसका आकार करीब 120 करोड़ रुपये बताया गया है। यह तीनों कंपनियों में सबसे बड़ा एसएमई इश्यू होगा। यजूर फाइबर्स जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी का लक्ष्य अपने कारोबार का विस्तार कर बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। यह आईपीओ भी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा।

कुल मिलाकर वर्ष 2026 की शुरुआत में प्राथमिक बाजार में भले ही रफ्तार धीमी दिखाई दे रही हो, लेकिन इसे अस्थायी चरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बाजार की दिशा स्पष्ट होगी, वैसे-वैसे आईपीओ गतिविधियों में तेजी आएगी। फिलहाल एसएमई सेगमेंट की ये तीन कंपनियां नए साल में निवेशकों की धारणा को परखने का काम करेंगी और आने वाले महीनों के लिए बाजार की दिशा का संकेत भी देंगी।

वाराणसी में कॉलोनाइजर हत्याकांड का पर्दाफाश: एक लाख रुपये के इनामी शूटर गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में घायल

(जीएनएस)। वाराणसी। शहर में लंबे समय से चर्चा में रहे कॉलोनाइजर महेन्द्र गौतम हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कुख्यात मामले से जुड़े एक लाख रुपये के इनामी शूटर अरविन्द यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गिरफ्तारी ने न केवल हत्याकांड में नया मोड़ लाया है बल्कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तत्परता को भी उजागर किया है। पुलिस के मुताबिक, सारनाथ थाना पुलिस और विशेष जांच टीम (एसओजी) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की। गुप्त सूचना मिली थी कि कॉलोनाइजर महेन्द्र गौतम की हत्या में शामिल इनामी शूटर अपने एक साथी के साथ सरायमोहना–सलारपुर क्षेत्र में गंगा किनारे मौजूद हैं। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी की और संदिग्धों की हरकतों पर नजर रखने लगी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध पुलिस की नजर में आए। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अरविन्द यादव घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। घटना स्थल से पुलिस ने दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और 750 रुपये नकद बरामद किए। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिमराफैज, कोतवाली गाजीपुर का निवासी अरविन्द यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शूटर का कुख्यात अपराधी बनारसी यादव के साथ गहरा संबंध है और पिछले कई वर्षों से पुलिस की नजर में था। डीसीपी ने आगे कहा कि मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों ने कानून और मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए कार्रवाई की। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

वाराणसी पुलिस ने इस मामले में विशेष टीमें गठित की हैं, जो फरार साथी की तलाश में लगे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस अभियान के तहत पूरे वाराणसी में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस कार्रवाई को शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर संतोष का माहौल है। कॉलोनाइजर महेन्द्र गौतम हत्याकांड ने इलाके में डर का वातावरण बना रखा था। इस गिरफ्तारी से लोगों को उम्मीद है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में इस तरह की वारदातों को रोका जा सकेगा।

सारनाथ थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, एसओजी प्रभारी गौरव सिंह, चौकी प्रभारी राहुल यादव और सरायमोहना चौकी इंचार्ज अनुज शुक्ला सहित अन्य पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार शूटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसके साथी की गिरफ्तारी के प्रयास और तेज किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की मुठभेड़ें पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। इसमें तुरंत निर्णय लेने, अपराधियों के संभावित हथियार और इलाके की स्थिति का आंकलन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

मांडवी में इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा, राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली ने विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण

(जीएनएस)। सूरत जिले के मांडवी तालुका में वन, पर्यावरण और ग्रामीण विकास को एक साथ सशक्त बनाने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जब गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली ने सूरत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मांडवी साउथ रेंज अंतर्गत दो प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में केवड़ी इको-टूरिज्म साइट पर विसडालिया क्लस्टर के अंतर्गत स्थापित 'रूरल मॉल' आउटलेट तथा मांडवी रेंज के गुली उमर फॉरेस्ट चौकी परिसर में निर्मित अत्याधुनिक वाइल्ड पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर शामिल हैं। दोनों परियोजनाओं पर कुल 65 लाख रुपये की लागत आई है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गुली उमर फॉरेस्ट चौकी में 50 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए वाइल्ड पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री प्रवीणभाई माली ने कहा कि यह केंद्र वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के ब्रीडिंग सेंटर दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण में सहायक होते हैं

और इससे भविष्य में वन्यजीव संतुलन को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात सरकार पर्यावरण संरक्षण को केवल नीति तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्य कर रही है। इसके साथ ही केवड़ी इको-टूरिज्म साइट पर 15 लाख रुपये की लागत से स्थापित 'रूरल मॉल' आउटलेट का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री माली ने कहा कि यह रूरल मॉल ग्रामीण, आदिवासी और वनवासी समुदायों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खोलेगा। यहां स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे पर्यटकों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उत्पादकों को उचित मूल्य मिलेगा। उद्घाटन के बाद राज्य मंत्री ने केवड़ी इको-टूरिज्म साइट पर आए पर्यटकों से संवाद किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, मार्गदर्शन और प्राकृतिक अनुभव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्होंने वन अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए, ताकि इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। इसके पश्चात मंत्री ने मांडवी साउथ रेंज के वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और गुली उमर फॉरेस्ट चौकी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

केवड़ी इको-टूरिज्म साइट पर स्थापित विसडालिया क्लस्टर का 'रूरल मॉल' विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरेगा। यहां हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं, बांस से तैयार फर्नीचर, बेकरी उत्पाद, मसाले, पापड़, मशरूम, आयुर्वेदिक और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इससे विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी और उनकी आय में स्थायी वृद्धि होगी। 'द रूरल मॉल' के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी पहचान मिलेगी। इस अवसर पर विधायक कुंवरजीभाई हलपति, सूरत सर्कल के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स पुनीत नैयर, भरूच सर्कल (सोशल फॉरेस्ट्री) के कंजर्वेटर आनंद कुमार, सूरत सोशल फॉरेस्ट्री की डिप्टी कंजर्वेटर मित्तल सावंत, व्यारा के डिप्टी कंजर्वेटर सचिन गुप्ता, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एच. जे. वांडा, असिस्टेंट कंजर्वेटर एच. आर. जादव सहित वन विभाग के अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान वन संरक्षण, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों के विकास को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला। मांडवी में शुरू की गई ये परियोजनाएं आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होने की उम्मीद जगाती हैं।

स्वस्थ जीवन की कुंजी हैं छोटी-छोटी अच्छी आदतें, हेल्थ सेमिनार में डॉ. आर. एन. वर्मा का संदेश

(जीएनएस)। तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव और असंतुलित खानपान आज समाज के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की ओर से रविवार, 4 जनवरी 2026 को द्वारका हॉल, महाराज अग्रसेन भवन, सिटी लाइट, सूरत में 43वें हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 11:45 बजे तक चले इस सेमिनार में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के विचार सुने। परिषद के संस्थापक श्रीकांतजी मूंदड़ा ने बताया कि यह सेमिनार परिषद की निरंतर चल रही स्वास्थ्य जागरूकता मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य संदेश पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉ. आर. एन. वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में केवल इच्छाशक्ति से स्वस्थ रहना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक सोच, तर्क

और प्रमाणों के आधार पर जीवनशैली अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास, अधूरी जानकारी और गलत आदतें ही अनेक बीमारियों की जड़ बनती हैं। डॉ. वर्मा ने अपने विस्तृत व्याख्यान में इस बात पर विशेष जोर दिया कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत से ही आकार लेने लगता है। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के समय मां का पोषण, मानसिक स्थिति और दिनचर्या गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मां द्वारा लिया गया संतुलित आहार शिशु के मस्तिष्क, हड्डियों, अंगों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। गर्भकाल के दौरान की गई लापरवाही भविष्य में बच्चे के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है।

उन्होंने गर्भावस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी देते हुए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन, खनिज तत्वों और पर्याप्त पानी के सेवन को अनिवार्य बताया। साथ ही उन्होंने जंक फूड, अत्यधिक तला-भुना भोजन, नशीले पदार्थों के सेवन, बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाइयों के उपयोग, तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचने की सलाह दी। उनका कहना था कि स्वस्थ मां से ही स्वस्थ शिशु का जन्म संभव है और गर्भावस्था के नौ महीने बच्चे के पूरे जीवन के स्वास्थ्य की नींव रखते हैं।

डॉ. वर्मा ने आगे कहा कि केवल गर्भावस्था ही नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण में संतुलित और पारंपरिक भारतीय आहार को अपनाना अत्यंत लाभकारी है। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध, दही और मेवों से युक्त भोजन शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, जबकि जंक फूड और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ धीरे-धीरे शरीर को बीमारियों की ओर धकेलते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रोकथाम इलाज से कहीं बेहतर है और यदि लोग समय रहते छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपना लें, तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा और मानसिक तनाव जैसी अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित डॉ. जी. एस. सोनी ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारतीय जीवनशैली केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से संतुलित जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि यदि आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच भी भारतीय दिनचर्या, जैसे समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और मानसिक संतुलन को अपनाया जाए, तो जीवन अधिक स्वस्थ और संतुलित बन सकता है।

सेमिनार के दौरान उपस्थित श्रोताओं ने वक्ताओं के विचारों को गंभीरता से सुना और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रश्न भी पूछे। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीकांत मूंदड़ा, बिनय अग्रवाल, मनमोहन मूंदड़ा, अतुल बागड़, श्याम चांडक सहित परिषद की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।